कई सारे लोगों और मुख्य सरकारी विभागों के व्यक्तियों तथा बहुपक्षीय एजेंसियों से भी मुलाकात की है।

(घ) मंत्रीमंडलीय / सचिव के नेतृत्व में संयुक्त सरकारी / व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने जून 1997 में 7 कार्य दिवसों (8 से 18 जून 1997 के बीच) सं० राज्य अमेरिका का दौरा किया था। सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम निम्नवत है:—

1. श्री टी० एस० आर० सुब्रमणियन, मंत्रीमंडलीय सचिव
2. श्री एन पी० बागची सचिव कोयला मंत्री
3. श्री योगेन्द्र नारायण, सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय
4. डा० शंकर एन आचार्य मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय।
5. श्री श्याम लाल घोष, सचिव इलैक्ट्रानिक विभाग (केवल सैन जोस)
6. श्री प्रदीप बैजल, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय
7. डॉ अविनाश चन्द्र, महानिदेशक, हाइड्रो कार्बन, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
8. श्री धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिवालय।

व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम निम्नवत है।

1. श्री अनिल अमानी, प्रबंधक निदेशक, रिलायन्स इंडेस्ट्री
2. श्री के० के० मोली, अध्यक्ष, मोदी इंटरप्राइजेज
3. श्री के० जी० रामानाथन, सीएमडी आई०पी०सी०एल बड़ौदा
4. श्री अशोक अग्रवाल, निदेशक टीसीआई इन्फ्राइन्ट्रक्सन फाइनेस लि०
5. श्री सी० दास गुप्ता, उप प्रबंध निदेशक, सीईएससी लि०
6. डा० सोम दत्त, सोमदत्त बिल्डर्स
7. श्री सी० एल० वर्मा, सीएमडी, कौन्टीनेन्टल कन्ट्रक्सन लि०
8. श्री के० एन० शिनाय, कार्यकारी अध्यक्ष, एबी बी लि०
9. श्री आर० सेशासायी, उप प्रबंध अशोक लिलैण्ड लि०
10. श्री ए० रामाकृष्णा, अध्यक्ष (प्रचालन) लारसन एण्ड टबरो।
11. डॉ अशोक हारने, मुख्य कार्यकारी, पावर बिजनिस ग्रुप आईएलएफएस
12. श्री एस चन्द्रशेखर, प्रबंध निदेशक, भूस्का पावर कारपोरेशन लि०

(ङ) निजी विद्युत नीति भारत के विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अपनी पूंजी निवेश करने की अनुमति प्रदान करती है।

विद्युत की तुलनात्मक कीमतें

569. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बतोन की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1997 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में "ऑफ पावर रिफार्म्स एण्ड काम्पिटीशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाय गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अमरीका और ब्रिटन में आई० पी० पी० बिजली की कीमत 1.40 रुपये तथा 1.60 रुपये प्रति कि० वा० है जो निरंतर प्रतिस्पर्धा के कारण और कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत में ये कीमतें 2.20 से 2.50 रुपये प्रति कि० वा० तक है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निजी क्षेत्र के बिजली क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण उपरोक्त कीमतों में और भी वृद्धि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य (श्री योगेन्द्रकुमार भगतराम अलघ): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) किसी विद्युत उत्पादन कम्पनी की टैरिफ का निर्धारण भारत सरकार की 30.3.92 (क्या संशोधित) की टैरिफ अधिसूचना के अनुसार किया जाएगा। एक विद्युत स्टेशन की टैरिफ उसकी समापन लागत, प्रौद्योगिकी, वित्त-पोषण का तरीका, ब्याज दर, प्रकार, ईंधन का मूल्य व स्रोत, ईंधन एवं उपस्कर पर कर और शुल्क, समापन का वर्ष, बिजली की कीमत

तथा कानून एवं नियन्त्रण आदि जैसे घटकों पर निर्भर करता है। ये घटक विभिन्न संयंत्रों और देशों की टैरिफों में समानता को जटिलतम बना देता है।

Power Requirement of Karnataka

570. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the MINISTER OF POWER be pleased to state:

(a) the total requirment of power in Kernataka:

(b) what is the total generation of power in Karnataka during last three years;

(c) what is the total allocation of power to Karnataka from the central grid during the last three years; and

(d) what are the steps taken by Government of Karnataka to generate more power and how many power plants are under installation in Karnataka?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) the energy and power requirment in Karnataka during 1996-97 was 24940 MU and 4220 MW respectively.

(b) The total energy generation in Karnataka during the years 1994-95, 1995-96 and 1996-97 was 16352 MU, 14915 MU and 12339 MU respectively,

(c) Entitlment versus actual drawal of power by Karnataka from central sector stations in southern region from 1994-95 to 1996-97 is given below:—

(Figures in MU)

	1994-95	1995-96	1996-97
Entitlement	4060	4085.9	4681.0
Actual Drawal	3395.2	4495.6	5773.7

(d) Government of Karnataka have evolved long term and short term measures to mitigate the shortage of power in the State.

SHORT TERM MEASURES

(1) Establishing Barge mounted power stations at four places with a total installed capacity of 606 MW.

(2) Establishing multi fuel projects of small capacity (20-50 MW) in twelve locations with a total capacity of 668 MW.

(3) KPCL is augmenting the capacity of their Thermal Plant at Raichur by adding two more units of 210 MW each.

(4) Hydro electric project Kodsalli and Sharavathi tail race projects are in advanced state of construction (360 MW).

LONG TERM MESURES

Government of Karnataka singed MOUs for establishing 19 projects with a total installed capacity of 6858 MW.

Four projects are under installation viz. Kadra—IInd phase (50 MW), Kodasalli, Raichur Thermal Power Station Vth and VIth units and Sharavathi tail race projects.

Loans on Concessinal Rates by Rural Electrification Corporation

571. SHRI PARAG CHALIHA: Will the MINISTER OF POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that louns on concessional rates are provided by the Rural electrification Corporation, under the Minimum Need Progoramme: and